

दिल्लीa विकास प्राधिकरण (योजना समन्वय इकाई)

सार्वजनिक सूचना

दिल्लीन विकास प्राधिकरण पैनल बनाने हेतु ऐसे इच्छुक नगर योजना पेशेवरों/योजना/आधारिक संरचना फर्मों/एजेंसियों से रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) आमंत्रित करता है, जिनके पास शहरी क्षेत्रीय योजना, नगर योजना, आधारिक संरचना एवं बड़े भूखण्डों के नियोजित विकास के क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता हो। आवेदक/एजेंसी/फर्म के पास इस प्रकार की प्रकृति/पैमाने की परियोजना का संचालन करने के लिए आवश्यक आधारिक संरचनात्मक सुविधाएँ, प्रबंधन संबंधी कौशल और अपेक्षित कर्मचारी होने चाहिए। अपेक्षित प्रबंधन संरचना, व्याधवसायिक अनुभव एवं विशेषज्ञता विभिन्न क्षेत्रों जैसे राजस्व योजना आदि में क्षमता/सामर्थ्य आदि का विवरण आवेदन-पत्र के निर्धारित प्ररूप में मुहरबंद लिफाफे में 25.2.2019 तक अथवा उससे पहले आयुक्तन (योजना) 5 वाँ तल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टे)द नई दिल्ली-110002 को भेजा जाना चाहिए। विवरण डाउनलोड करने हेतु दि.वि.प्रा. की वेबसाइट अर्थात् www.dda.org.in पर उपलब्धि है।

फाइल सं. एफ. 11(30)2019/प्लाबनिंग/कोर्डि

दिनांक:

आयुक्तं (योजना)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नगर योजना पेशवरों/परामर्शी योजना/आधारिक संरचना फर्मों/एजेंसियों से

रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने की सूचना

1. उद्देश्य:

दिल्ली जो भारत के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का केन्द्र है और प्राचीन मूल्यों एवं आकांक्षाओं का प्रतीक है तथा सबसे बड़े प्रजातंत्र की राजधानी है, विश्वा के प्रमुख शहरों के बीच बढ़ती हुई प्रतिष्ठार प्राप्त कर रही है।

दिल्ली को एक वैश्विक महानगर और एक विश्व स्तहरीय शहर बनाने का लक्ष्य है। सभी व्यक्त एक अच्छे वातावरण में बेहतर जीवन-स्तकर के साथ उत्पायदक कार्यों में व्यजस्त रहेंगे।

दिल्लीय विकास प्राधिकरण को दिल्लीा मुख्य योजना-2021 के अनुसार भूमि नीति के माध्यम से जोन जे, के-1, एल, एन एवं पी (I एवं II) के शहरीकरण योग्य क्षेत्र में आने वाली भूमि के शहरीकरण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। भूमि नीति को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा का.आ. 5220 (ई) दिनांक 11.11.2018 द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस नीति के प्रचालन हेतु विनियमों को दिल्लीी विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली1 विकास अधिनियम-1957 की धारा 57 के अंतर्गत का.आ. 5384 (ई) दिनांक 24.10.2018 द्वारा अधिसूचित किया गया है। भूमि नीति के अतिरिक्त दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में बड़े भूखण्ड खाली पड़े हुए हैं। इनके लिए व्यापक योजना की आवश्यकता है। दि.मु.यो.-2021 में पुनर्विकास के रूप में विद्यमान शहरी क्षेत्रों की योजना और सघनता वाले आवासीय क्षेत्रों हेतु नीति, निजी भूमि नीति, ट्रांजिट ओरिएण्टेड डिवेलपमेंट पॉलिसी जैसी अन्य नीतियों के क्रियान्वेयन पर विचार किया गया है।

प्रस्तावित है कि उपर्युक्त कार्य को ऐसी प्राइवेट एजेंसियों द्वारा करवाया जा सकता है जिनके पास इस प्रकार के कार्यों को करने की विशेषज्ञता हो।

2. विचारार्थ विषय:

- (i) दिल्ली के विकास के लिए नए और आधुनिक विचारों को शामिल करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण पैनल बनाने के लिए ऐसे इच्छुक नगर योजना पेशवरों/परामर्शी योजना/आधारिक संरचना फर्मों/एजेंसियों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है,

जिनके पास शहरी क्षेत्रीय योजना , नगर योजना, आधारिक संरचना और बड़े भूखण्डों के नियोजित विकास के क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता हो।

- (ii) रूचि की अभिव्यक्ति मूल्यां कन के अधीन होगी और केवल उन्हें ही सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसके दस्तारवेज मूलतः अनुकूल होंगे। कृपया ध्यागन दें कि इस रूचि की अभिव्यक्ति द्वारा दि.वि.प्रा. की ओर से कार्य सौंपने अथवा दस्तारवेजों की लागत वहन करने की कोई वचनबद्धता नहीं दी जा रही है।
- (iii) एजेंसी की कार्य करने की वैधता 3 वर्ष की अवधि तक रहेगी और उसे बढ़ाया जा सकता है।
- (iv) चयनित एजेंसियों को परियोजना के सुचारु कार्यान्वायन के लिए व्यागपक कार्य करने और योजना के प्ररूपण हेतु परियोजनाओं की स्की मों आदि की जानकारी के संबंध में दि.वि.प्रा. के संबंधित विभाग द्वारा जानकारी प्रदान की जाएगी।
- (v) आवेदक, जिनके पास बहुविषयक क्षेत्रों , तकनीकी का उपयोग एवं जी.आई.एस. आधारित सॉफ्टवेयर के प्रयोग का अनुभव है, को वरीयता दी जाएगी।

3. अर्हता मानदण्डत

- (i) आवेदक/फर्म के अग्रणी सदस्यक को इन्स्टिट्यूट ऑफ टाउन प्ला.नर ऑफ इण्डिया में पंजीकृत होना चाहिए अथवा फर्म इण्डिया कंपनी एक्टस और/अथवा किसी सरकारी , अर्धसरकारी, स्वा यत्त और/अथवा योजना क्षेत्र में नियमित निकाय के अधीन पंजीकृत होनी चाहिए।
- (ii) आवेदन/फर्म 31 मार्च 2018 को कम से कम पाँच वित्तीय वर्षों तक भारत में प्रचालन में होना चाहिए।
- (iii) रूचि की अभिव्यक्ति में मानव शक्ति और उपलब्ध आधारिक संरचना संबंधी विवरण आवश्यांक रूप से होने चाहिए।
- (iv) आवेदक को रा.रा. क्षे. दिल्ली में प्रचलित मुख्यस योजना , क्षेत्रीय योजना , नियमों, विनियमों, उपविधियों और विभिन्न अधिनियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए।

- (v) आवेदक को संलग्न प्रोफॉर्मा के अनुसार प्रारंभिक योग्यता हेतु समर्थन दस्तारवेज प्रस्तुत करने चाहिए।
- (vi) बोली सभी योग्यता मानदण्डों के अनुरूप होनी चाहिए , कोई बोली जो मानदण्डों के अनुरूप नहीं है उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (vii) दि.वि.प्रा. क्रीडेंशियल/दावों के वास्तविक सत्यापन हेतु फर्म संस्थापना का दौरा कर सकता है।
- (viii) आवेदक/फर्म को केन्द्र/राज्य सरकार विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी एजेंसियों द्वारा काली सूची में दर्ज/बहिष्कृत नहीं होना चाहिए।

4. सामान्यी शर्तें

- (i) अपर्याप्त सूचना प्रस्तुत करने और उपर्युक्त शर्तों का पूरी तरह से पालन नहीं करने पर आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिए जाएँगे।
- (ii) दि.वि.प्रा. को बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी रुचि की अभिव्यक्तियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार है और ऐसा निर्णय लेने पर बाद में उसका कोई दायित्वा चाहे कुछ भी हो, नहीं होगा।
- (iii) दि.वि.प्रा. अपने विवेकाधिकार से प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।
- (iv) दि.वि.प्रा. अपने विवेकाधिकार से किसी भी समय दस्ता वॉर्जों से जुड़ी चयन प्रक्रिया को रोक सकता है।
- (v) दि.वि.प्रा. किसी बोलीदाता को संविदा/संविदाएँ देने के लिए अनिश्चितकाल के लिए अथवा निश्चित समयावधि के लिए अपात्र घोषित कर देगा, यदि किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि बोलीदाता ने इसमें भाग लेने में अथवा परामर्शी संविदा को निष्पादित करने में भ्रष्ट कपटपूर्ण कार्यप्रणाली अपनाई है।
- (vi) दि.वि.प्रा. अपने विवेकाधिकार से पैनल को तीन वर्ष की समाप्ति से पहले जारी/समाप्त कर सकता है।

- (vii) यदि बहुत अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं, तो दि.वि.प्रा. को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित/अनुमोदित मानदण्ड/टर्नओवर आदि के आधार पर एजेंसियों को स्वीधकार/अस्वीकार करने/चुनने का अधिकारी है।

5. प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण:

- (i) प्रस्ताव दिनांक 25.2.2019 को 3.00 बजे तक आयुक्ति (योजना) , 5 वीं मंजिल , दि.वि.प्रा., विकास मीनार, नई दिल्ली-110002 के कार्यालय में हार्ड कॉपी फॉर्मेट में जमा किया जाना चाहिए।
- (ii) प्रस्ताव केवल संलग्न फॉर्मेट के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (iii) रुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) पर किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण लिखित रूप में अथवा सीधे आयुक्तर (योजना) कार्यालय, 5 वॉ तल, दि.वि.प्रा., विकास मीनार, दूरभाष सं. 011-23379416, ई-मेल आई.डी. से प्राप्त किया जा सकता है।
- (iv) प्राप्ति की नियत तिथि के पश्चानत् प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा/उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (v) मुहरबंद लिफाफे के बाहरी तरफ सूचना “नगर योजनाकार/नगर योजना एजेंसियों/फर्म को पैनलबद्ध करने हेतु प्रस्ताव स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए।

6. चयन:

- (i) तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त और चुने गए आवेदकों/फर्मों का दि.वि.प्रा. के योजना विभाग में तीन (03) वर्ष के लिए पैनल बनाया जाएगा।

दिल्लीम विकास प्राधिकरण

विषय: रूचि की अभिव्यक्ति हेतु प्ररूप

1. नाम एवं पूरा पता:
2. पंजीकरण विवरण:
3. आधारिक संरचना एवं कर्मचारियों सहित प्रबंधन संरचना:
4. तकनीकी क्षमता:
5. पिछले तीन वर्ष का टर्न-ओवर:
6. वर्तमान कार्य-संचालन क्षेत्र:
7. किसी भी सरकार का अनुमोदन/पंजीकरण:
8. वह कार्य क्षेत्र, जिसमें विशेषज्ञता हो, कृपया विस्तार से बताएँ:
9. प्रस्तायवित कार्य हेतु रोल पर उपलब्ध नियमित कर्मचारी, उनकी अर्हता और अनुभव सहित:
10. विषय-क्षेत्र में कोई अन्यन प्रत्यतय-पत्र (क्रीडेंशियल):
11. पदनाम सहित व्यषक्ति से संपर्क संबंधी विवरण:
 - क. दूरभाष नं.
 - ख. मोबाइल नं.
 - ग. फैक्सल नं.
 - घ. ई-मेल पता